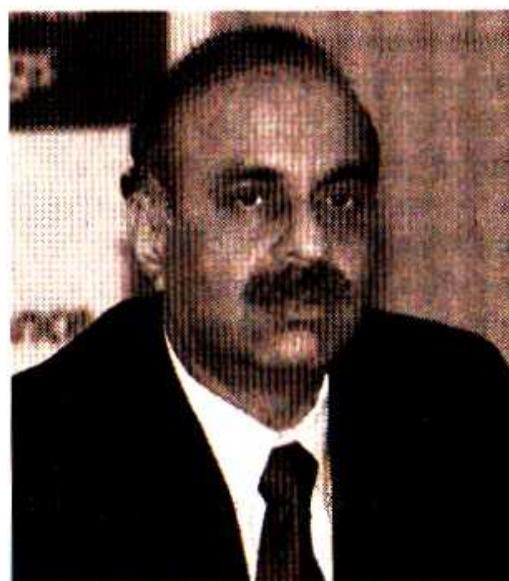


## ‘विलय व अधिग्रहण से होगा कारोबारी विस्तार’

पर्यूचर जेनेरली इंडिया इंश्योरेंस के अधिग्रहण से एलएंडटी के सामान्य बीमा कारोबार आकार और दायरे को गति मिलेगी जिससे तेजी से मुनाफे की स्थिति हासिल करने में मदद मिलेगी। एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक एन शिवरामन ने मनोजित साहा के साथ आगे की योजनाओं के बारे में बातचीत की। बातचीत के प्रमुख अंश:

किस आधार पर एलएंडटी ने इस सौदे की पहल की?

इस सौदे से हमें तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला है। मसलन 31 मार्च 2012 की समाप्ति तक हमारे सामान्य बीमा कारोबार से 143 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम हासिल हुआ जबकि पर्यूचर जेनेरली से करीब 1,100 करोड़ रुपये हासिल हुआ। निश्चित तौर पर रकम की मात्रा महत्वपूर्ण है। एक प्रयास से हम व्यापक तौर पर इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भविष्य में मुनाफे को गति मिलेगी। मौजूदा तौर पर पर्यूचर जेनेरली का कारोबार बढ़िया है और यह जल्द ही न तो मुनाफे और न ही घाटे की स्थिति में पहुंचने वाली है। हमने महसूस किया है कि विलय एवं अधिग्रहण के जरिये कारोबार के आकार और उसके दायरे को बढ़ाने का मकसद एक साथ पूरा किया जा



सकता है।

क्या आप विलय एवं अधिग्रहण की नीति पर काम करते रहेंगे?

इस रास्ते से आगे बढ़ने की नीति दो विचारों पर निर्भर करती है। पहला कि यह वह कारोबार होगा जिसमें हम उत्तरना चाहते हैं या फिर हम कम समय में बाजार तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि एकीकरण की संभावनाएं सामने आ सकती हैं। मसलन जब हमने फिडेलिटी का अधिग्रहण किया तो यह म्युचुअल फंड कारोबार के एकीकरण का अवसर था। वहीं दूसरी तरफ से इससे हमारे म्युचुअल फंड कारोबार का आकार भी बढ़ा हुआ। पर्यूचर जेनेरली का आकार हमारे मौजूदा स्वरूप से सात गुना बढ़ा है। इससे हमारे मुनाफे की स्थिति को भी बल मिलेगा।

कब से मुनाफे का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जाएगा?

दिसंबर 2012 तक समाप्त 9 महीनों के दौरान उनका संयुक्त संचालन अनुपात 102 फीसदी रहा है जो कि न तो मुनाफे और न ही घाटे की स्थिति के करीब है।

अधिग्रहण के बाद आपको कितनी बाजार हिस्सेदारी मिलेगी?

फिलहाल हमारी बाजार हिस्सेदारी 0.2 फीसदी है और संयुक्त तौर पर हमारी बाजार हिस्सेदारी 1.8 फीसदी होगी।

उपक्रम में एलएंडटी भविष्य में अपनी हिस्सेदारी में इजाफा करेगी?

बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर बातचीत जारी है और नीति निर्माताओं के बीच इसे 49 फीसदी किए जाने को लेकर बहस चल रही है। एलएंडटी का मानना है कि इस समय हमारा ध्यान संयुक्त इकाई में 51 फीसदी हिस्सेदारी पर होना चाहिए न कि 74 फीसदी तक जिसे नियमों में होने वाले बदलाव के बाद फिर से कम करना पड़ सकता है।

क्या आप बीमा नियामक की मंजूरी की शर्तों को पूरा कर चुके हैं? कब तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है?

शर्तों से जुड़े मसौदे पर अभी अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। हम अब नियामकीय प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नए दिशानिर्देशों के बाद यह पहला विलय होगा। मंजूरी को लेकर निर्धारित समयावधि के बारे में बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा।